

न्यूज ब्रीफ

मायके जाने की जिद पर विवाद, मां ने बच्ची संग गंगनहर में लगाई छलांग

भारतेंदु संवाददाता, हरिद्वार। पति-पत्नी के बीच मायके जाने की बात को लेकर हुए विवाद के बाद एक महिला ने अपनी एक वर्षीय बेटी को गोद में लेकर गंगनहर में छलांग लगा दी। घटना बहादुराबाद क्षेत्र की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ की टीम ने दोनों की तलाश के लिए अभियान शुरू किया। पुलिस के अनुसार महिला अपने मायके जाने की जिद कर रही थी जबकि पति अपनी बीमार मां से मिलने देहरादून जाना चाहता था। मामले की जांच जारी है।

रुद्रपुर में वाहनों की टक्कर, एक की मौत, चार घायल

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड के उधमसिंहनगर जिले के रुद्रपुर में सड़क वन रेलवे कोसिंग के समीप दो वाहनों की आमने-सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र की ओर से सोमवार को जारी बुलेटिन के अनुसार दुर्घटना रविवार रात करीब 11 बजे रुद्रपुर तहसील क्षेत्र में हुई। हादसे में पांच लोग घायल हुए थे, जिनमें से एक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

विवाहिता ने लगाया 35 लाख रुपये और लगजरी कार की मांग का आरोप, मुकदमा दर्ज

भारतेंदु संवाददाता, हरिद्वार। कनखल थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने पति और ससुरार पक्ष पर देहेज में 35 लाख रुपये और एक लगजरी कार की मांग करने के गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ मारपीट, मानसिक उत्पीड़न किया गया और उसे घर से निकाल दिया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पति, सास और ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कंडोली का मंत्री जोशी ने किया उद्घाटन

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, कंडोली में लवनिर्मित आयुर्वेद उर्कर्ष केंद्र का रिबन काटकर विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने आयुर्वेद उर्कर्ष केंद्र का अवलोकन कर वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं व व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। इस दौरान उन्होंने नेचुराद्वयिक भवन में लगाए गए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का भी उद्घाटन किया।

जनसुनवाई में 100 शिकायतें दर्ज, 55 का मौके पर निस्तारण

भारतेंदु संवाददाता, हरिद्वार। जनपदवासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हिस्सेन विभागों से संबंधित 100 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 55 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष मामलों को समयबद्ध कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया गया।

फॉरेस्ट में ऑल टूरिस्ट साइट्स के लिए ऑनलाइन होगी बुकिंग व्यवस्था

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्दधन ने सोमवार को सचिवालय में प्रदेश के अंतर्गत इको-टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ाए जाने को लेकर वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने पिछली बैठक में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में इको-टूरिज्म के लिए आर्थिक सम्भावनाएं हैं। इसे प्रदेश और प्रदेश के नागरिकों की आर्थिकी से जोड़े जाने की आवश्यकता है, ताकि बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए हम वनों को आजीविका से जुड़ी गतिविधियों से जोड़ सकें। मुख्य सचिव ने प्रदेश में ट्रेकिंग पोलिसी तैयार कर शीघ्र लागू किए जाने के निर्देश दिए हैं।

सीएम धामी ने सोमनाथ आस्था ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, 720 श्रद्धालुओं ने शुरु की यात्रा



आस्था ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते मुख्यमंत्री, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह।

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। देहरादून के हर्वावाला रेलवे स्टेशन से सोमवार को सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के तहत विशेष आस्था ट्रेन गुजरात स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ धाम के लिए रवाना हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्टेशन पहुंचकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस विशेष यात्रा में उत्तराखंड के 720 श्रद्धालु शामिल हुए हैं। उत्तराखंड सरकार के संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित इस यात्रा का उद्देश्य श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने के साथ राज्य की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के रूप में अपनी विशेष पहचान

गांवों की सुविधा के लिए ऋषिकेश विधायक ने की 600 लाइटों की घोषणा

डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल की घोषणा, गांवों में मजबूत होगी पथ प्रकाश व्यवस्था



भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। ऋषिकेश विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा क्षेत्र के समय विकास को गति देने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बड़ी घोषणा की है। ऋषिकेश स्थित कैप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विधायक निधि से लगभग 600 लाइटें उपलब्ध करने की जानकारी दी। इन लाइटों को विभिन्न जनप्रतिनिधियों के माध्यम से गांवों में स्थापित किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर रोशनी व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। डॉ. अग्रवाल ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य को 10 लाइट, प्रत्येक ग्राम प्रधान को 20

माय भारत अभियान को गति देगा चंपावत

माय भारत से जुड़े 2.2 करोड़ युवा, चंपावत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की तैयारी



अधिकारियों की मौजूदगी में योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित।

भारतेंदु संवाददाता, चंपावत। सोमवार को जनपद चंपावत में युवाओं को राष्ट्र निर्माण, नेतृत्व विकास, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर अवसरों से जोड़ने के उद्देश्य से एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक मुख्य विकास अधिकारी डॉ. गणेश सिंह खाती की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें ‘मेरा युवा भारत’ (युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार) की वार्षिक कार्ययोजना 2026–27 को विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य

विकास अधिकारी डॉ. गणेश सिंह खाती ने निर्देश दिए कि जनपद के प्रत्येक विकासखंड, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और युवा क्लब तक माय भारत की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा, ‘विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की ऊर्जा और नवाचार सबसे बड़ी ताकत हैं।’ सीडीओ ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ वार्षिक कार्ययोजना का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए।बैठक में उप

यूपीईएस में सीखने की नई पहल, प्रोजेक्ट ग्रो 2.0 का हुआ सफल समापन

यूपीईएस का प्रोजेक्ट ग्रो 2.0 सफलतापूर्वक पूरा, महिलाओं को मिला सशक्तिकरण का मंच

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून।

यूपीईएस ने समावेशी विकास और आजीवन सीखने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए प्रोजेक्ट ग्रो 2.0 को सफलतापूर्वक पूरा किया। स्कूल फॉर लाइफ एसएफएल, एसएफएल एम्बेसडर्स और मानव संसाधन टीम के संयुक्त प्रयास से संचालित इस पहल का उद्देश्य महिला हाउसकीपिंग स्टाफ की अंग्रेजी भाषा दक्षता और संवाद कौशल को मजबूत करना था। कार्यक्रम ने प्रतिभागियों को व्याक्तिगत विकास के अवसर प्रदान किए, वहीं छात्रों को भी वास्तविक परिस्थितियों में नेतृत्व और शिक्षण कौशल विकसित करने का मौका मिला।

प्रोजेक्ट ग्रो 2.0 को प्रोजेक्ट ग्रो 1.0 की सफलता के बाद शुरू किया गया। इसके दूसरे चरण में यूपीईएस के कंडोली परिसर में कार्यरत महिला



हाउसकीपिंग कर्मचारियों को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। कार्यक्रम के तहत रोजमर्रा की जरूरतों के अनुरूप भाषा प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिनमें अंग्रेजी भाषा की बुनियादी जानकारी, वाक्य निर्माण और प्रभावी संवाद कौशल सिखाया गया।

इस पहल का नेतृत्व एसएफएल एम्बेसडर्स अलेना वारिस और काशवी केडिया ने किया। उनके साथ कई छात्र सदस्यों ने सहयोग किया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर विपिन चौहान

के मार्गदर्शन में हुआ, जिसमें प्रोफेसर राशिका गोकुला और प्रोफेसर सूर्या सिंह का भी योगदान रहा।

कार्यक्रम का शुभारंभ 6 मार्च 2026 को विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। इस दौरान डॉ. अंत्रि नौटियाल, डॉ. गौरव मिश्रा, सुशी मेधा जैन और यूपीईएस समुदाय के अन्य सदस्यों ने भाग लिया। उन्होंने इस पहल को ऐसा प्रयास बताया जो शिक्षा को पारंपरिक कक्षाओं से आगे ले जाकर समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाता है।

◆ 15 अगस्त तक चलेगा युवा अभियान

◆ देश निर्माण में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की पहल

निदेशक शैलेश भट्ट ने माय भारत पोर्टल और भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि: देशभर में अब तक 2.2 करोड़ से अधिक युवा माय भारत पोर्टल से जुड़ चुके हैं।

अधिक से अधिक युवाओं को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले टॉप 3 जिलों को 15 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा।

चंपावत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिले के सभी शिक्षण संस्थानों

हरिद्वार में नकली नोट गिरोह का भंडाफोड़, 14 दिन में 12 तस्कर गिरफ्तार



भारतेंदु संवाददाता, हरिद्वार। धर्मनगरी हरिद्वार में नकली नोटों को खपाने की साजिश करने वाले एक बड़े गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने पिछले 14 दिनों में लगातार कार्रवाई करते हुए गिरोह के 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 2.92 लाख रुपये की नकली करेंसी के साथ नोट छापने में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर लैपटॉप मोबाइल और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं।

पुलिस जांच में सामने आया है कि यह गिरोह देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं और भीड़भाड़ वाले बाजारों को निशाना बनाने की योजना बना रहा था। आरोपी छोटे दुकानदारों और धार्मिक स्थलों के आसपास नकली नोट चलाने की फिराक में थे। पुलिस ने 28 जून को श्यामपुर थाना क्षेत्र से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था जिनके पास से 52 हजार 500 रुपये की जाली करेंसी मिली थी।

पूछताछ के आधार पर पुलिस ने आगे कार्रवाई करते हुए अन्य सदस्यों को भी पकड़ा। 6 जुलाई को नगर कोतवाली पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर 84 हजार 500 रुपये के नकली नोट बरामद किए। बाद में पंजाब में छापेमारी कर दो और आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है।

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्टेशनों पर बग्गे होल्डिंग एरिया

कुंभ में भीड़ नियंत्रण के लिए 10 रेलवे स्टेशनों को किया जाएगा तैयार



भारतेंदु संवाददाता, हरिद्वार। कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार हरिद्वार और ऋषिकेश समेत आसपास के 10 रेलवे स्टेशनों को कुंभ संचालन योजना में शामिल किया जा रहा है। इन स्टेशनों पर यात्रियों के लिए टिकट व्यवस्था पेयजल शौचालय प्रतीक्षालय सुरक्षा और प्रकाश व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार हरिद्वार के अलावा ऋषिकेश योगनगरी हर्वावाला रायवाला मोतीचूर ज्वालापुर पथरी लक्खर और रुड़की रेलवे स्टेशनों का इस्तेमाल यात्रियों को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा। इन स्थानों पर होल्डिंग एरिया और यात्री सूचना प्रणाली की सुविधा भी विकसित की जाएगी।

कुंभ के दौरान विशेष ट्रेनों के संचालन के साथ कई नियमित ट्रेनों के स्थानीय स्टेशनों पर अस्थायी ठहराव की योजना बनाई जा रही है। इससे श्रद्धालुओं को केवल हरिद्वार स्टेशन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और भीड़ का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। रेलवे राज्य सरकार और जिला प्रशासन के बीच समन्वय से पूरी कार्ययोजना तैयार की जा रही है। कई स्टेशनों पर सुरक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने का काम भी शुरू हो चुका है।

कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, विकास भवन द्वितीय तल, नई टिहरी।

पत्रांक /476/ ग्राफि0नि0 / निविदा सूचना/2026-27

अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या 4/2026-27

महामहिम राज्यपाल, महोदय उत्तराखण्ड, की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न कार्यों की सीलबन्द निविदायें निम्न तालिका के कॉलम 9 के अनुसार पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 28.07.2026 को 2.00 बजे अपराह्न तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में आमन्त्रित की जाती है, जो कि उसी दिन सायं 3:00 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपस्थित ठेकेदारों अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 27.07.2026 को सायं 4:00 बजे तक निर्धारित शुल्क का ई-चालान लेखाशीर्षक 0515008000100 (जिस पर कार्य का नाम अंकित हो, ही मान्य होगा) एवं जी0एस0टी0 शुल्क का चालान GST No. 05MRTR01108C1DJ में ई चालान के माध्यम से शुल्क जमा करा कर ई-चालान की प्रति प्रखण्ड कार्यालय टिहरी में उपलब्ध कराकर प्राप्त की जा सकती है।

क्रं. सं.	कार्य का नाम	विकास खण्ड का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)	धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा की वैधता	कार्यपूर्ण करने की अवधि	ठेकेदारों की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	विकास खण्ड नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत राजकीय पशु चिकित्सालय मुनीकैरेती में अनावासीय भवन का मरम्मत कार्य।	नरेन्द्रनगर	19.33	38660.00	1500.00 +18% जी0एस0टी0	45 दिन	04 माह	श्रेणी 'ई' एवं उच्चतर (भवन निर्माण कार्य हेतु)

निविदा की शर्तों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं।

अधिशासी अभियन्ता

ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड टिहरी।

ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने की जरूरत : राज्यपाल गुरमीत सिंह



राज्यपाल से मुलाकात के दौरान सम्मान और संवाद का भावपूर्ण क्षण।

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेन) के समक्ष नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में जीएनए एनजी के प्रबंध निदेशक संजीव कुमार और उनकी टीम ने ऊर्जा संरक्षण तथा डेटा विश्लेषण आधारित विद्युत प्रबंधन को लेकर प्रस्तुति दी। इस दौरान तकनीक और आधुनिक डेटा विश्लेषण के माध्यम से बिजली की बचत, संसाधनों के बेहतर उपयोग और ऊर्जा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रस्तुति में बताया गया कि डेटा आधारित तकनीकों के इस्तेमाल से

विद्युत क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाई जा सकती है और ऊर्जा की खपत को अधिक कुशल तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। इससे संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करने व साथ भविष्य की जरूरतों के अनुरूप ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने में सहायता मिलेगी।

राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नवाचार, तकनीक और डेटा आधारित समाधानों को बढ़ावा देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ऐसी पहलें ऊर्जा प्रबंधन को अधिक सक्षम और पारदर्शी बनाने के साथ-साथ आत्मनिर्भर व्यवस्था विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

मॉनसून सत्र में बिना शर्त महिला आरक्षण लागू करने की मांग तेज

भारतेंदु संवाददाता, हल्द्वानी। हल्द्वानी के बिंदुखत्ता में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन ऐपवा की बैठक आयोजित हुई। इसमें संसद के आगामी मॉनसून सत्र में महिला आरक्षण बिल को बिना शर्त लागू करने की मांग उठाई गई। ऐपवा की राष्ट्रीय सचिव श्वेता राज ने कहा कि सरकार को 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को जल्द लागू करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इसे परिसीमन से जोड़कर टाला जा रहा है। उत्तराखंड संयोजक डॉ. शिवानी पांडेय ने कहा कि महिलाओं को आगामी चुनावों में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। बैठक में महिला सुरक्षा और बढ़ते अपराधों पर भी चिंता जताई गई। ऐपवा ने 21 जुलाई को धरना-प्रदर्शन करने की घोषणा की। निर्मला शाही ने कहा कि, राज्य में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके खिलाफ महिलाओं को संगठित होने की जरूरत है।

प्रधानमंत्री मोदी के 5एफ विजन से बदलेगा वस्त्र उद्योग का भविष्य

◆ वस्त्र उद्योग बनेगा आर्थिक विकास का बड़ा आधार

का माध्यम है और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है। भारत टेक्स 2026 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5एफ विजन फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फारेन के संगम को दर्शा रहा है। कश्मीरी पश्मीना, असम का मूंगा सिल्क, राजस्थान की बांधनी और कांजीवरम सिल्क जैसे पारंपरिक वस्त्रों से लेकर आधुनिक तकनीकी वस्त्रों तक भारत की पूरी मूल्य श्रृंखला एक ही मंच पर दिखाई दे रही है।

वस्त्र उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है। यह क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में बड़ा योगदान देता है। कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाले क्षेत्रों में शामिल वस्त्र उद्योग करोड़ों लोगों की आजीविका

कार्यक्रम में वस्त्र क्षेत्र से जुड़े व्यापार, निवेश, तकनीक, नवाचार और स्थिरता जैसे विषयों पर चर्चा की जा रही है। विभिन्न सत्रों में उद्योग विशेषज्ञ, नीति निर्माता और वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधि भविष्य की रणनीतियों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री दौरे से पहले बम धमकी, बढ़ी सुरक्षा

मोहाली के स्कूलों, रेलवे स्टेशनों और मेयर कार्यालय को धमकी मिलने के बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाकर जांच की शुरु

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 17 जुलाई के प्रस्तावित चंडीगढ़ दौरे से पहले एक धमकी भरे ईमेल ने पंजाब, चंडीगढ़ और मोहाली की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। ईमेल में मोहाली के कई निजी स्कूलों, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, जालंधर रेलवे स्टेशन और मोहाली मेयर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सूचना सामने आते ही पुलिस, खुफिया एजेंसियों, रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी और साइबर विशेषज्ञों को तुरंत सक्रिय कर दिया गया। सभी संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पूरे मामले की बहुस्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। धमकी भरे ईमेल में केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का भी उल्लेख किया गया है। ईमेल भेजने वाले ने दावा किया है कि 17 जुलाई को दोपहर 1:11 बजे मोहाली के निजी स्कूलों में, 3:11 बजे मोहाली



गए हैं। ईमेल किस सचर्व से भेजा गया, उसमें किसी प्रकार की पहचान छिपाने की तकनीक का इस्तेमाल हुआ या नहीं और उसका वास्तविक स्रोत क्या है, इसकी पड़ताल की जा रही है। जांच एजेंसियां ईमेल की डिजिटल ट्रेल, आईपी संबंधी तकनीकी जानकारी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही हैं ताकि भेजने वाले तक जल्द पहुंचा जा सके।

जाएगा और प्रत्येक सूचना का पूरी गंभीरता से सत्यापन किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, हाल के महीनों में पंजाब और चंडीगढ़ के कई स्कूलों को इसी तरह के धमकी भरे ईमेल मिल चुके हैं। उन मामलों में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया था, लेकिन कहीं भी कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली थी। इसके बावजूद ऐसे मामलों को केवल अफवाह मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए समय रहते सतर्क रहना आवश्यक है। सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु, लावारिस बैग या संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर तुरंत पुलिस या संबंधित सुरक्षा एजेंसी को सूचना दें। साथ ही सोशल मीडिया पर अपुष्ट सूचनाएं या अफवाहें साझा करने से बचें, ताकि अनावश्यक दहशत का माहौल न बने।

रीसेल प्लॉट खरीदार को मिली राहत, बिल्डर लौटाएगा ब्याज सहित अतिरिक्त ईडीसी राशि

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली।

मोहाली जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिष्ठान आयोग ने एटीएस एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड और एटीएस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को बाढ़ा विकास शुल्क (ईडीसी) के नाम पर अधिक राशि वसूलने के मामले में बड़ा झटका देते हुए शिकायतकर्ताओं के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने दोनों कंपनियों को 1,65,943 रुपये 24 जून 2022 से नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा मानसिक प्रताड़ना और मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में 20 हजार रुपये का अतिरिक्त भुगतान भी करने का निर्देश दिया गया है। आयोग ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि रीसेल में संपत्ति खरीदने वाला व्यक्ति भी उपभोक्ता की श्रेणी में आता है और उसे बिल्डर के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराने का पूरा अधिकार है।

मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता शशि भूषण मित्तल और रेणु मित्तल ने वर्ष 2021 में डेराबस्सी स्थित एटीएस गोल्फ मेडोज-2 परियोजना में 350 वर्ग गज का प्लॉट मूल आवंटियों से खरीदा था।



आयोग ने बिल्डर की दलीलें की खारिज

आयोग ने कहा कि विवाद नगर परिषद द्वारा वसूले गए ईडीसी का नहीं, बल्कि बिल्डर द्वारा अधिक राशि लेकर उसे अपने पास रखने का है। इसलिए नगर परिषद को मामले में पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं था। आयोग ने बिल्डर के उस पत्र को भी अहम साक्ष्य माना, जिसमें शिकायतकर्ताओं को नगर परिषद में 2,42,382 रुपये ईडीसी जमा कराने के निर्देश दिए गए थे। इससे स्पष्ट हुआ कि वास्तविक देय ईडीसी पहले वसूली गई राशि से काफी कम थी और 1,65,943 रुपये बिना किसी वैधानिक आधार के रोककर रखे गए। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि बिल्डर का यह कृत्य सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर आयोग ने कंपनियों को निर्देश दिया कि वे शिकायतकर्ताओं को 1,65,943 रुपये 24 जून 2022 से नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाएं। साथ ही मानसिक प्रताड़ना और मुकदमेबाजी खर्च के लिए 20 हजार रुपये का भुगतान भी करें। आयोग के इस फैसले को रीसेल में संपत्ति खरीदने वाले उपभोक्ताओं के अधिकारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

एफबीआई रिपोर्ट में बिश्नोई और भगवानपुरिया गिरोहों के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का बड़ा खुलासा

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

कभी एक-दूसरे के करीबी रहे गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया के संगठित अपराध नेटवर्क को लेकर अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में कई गंभीर खुलासे सामने आए हैं। अमेरिका के न्याय विभाग (यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस) और एफबीआई की जांच से जुड़े दस्तावेजों के अनुसार दोनों गैंग अपने अपराधों को अंजाम देने के लिए नाबालिगों, आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं और महिलाओं का इस्तेमाल करते थे। जांच में यह भी सामने आया कि इंटरनेट मीडिया के जरिए युवाओं को पैसे, पहचान और सुरक्षा का लालच देकर गिरोह से जोड़ा जाता था तथा उन्हें हत्या, रंगदारी, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों के गतिविधियों में लगाया जाता था।

एफबीआई के ऑपरेशन हार्ड बॉल के तहत लॉस एंजेलिस की संघीय अदालत में पेश 44 पन्नों के अभियोग पत्र में दावा किया गया है



कि जग्गू भगवानपुरिया गैंग भारत के कुछ क्षेत्रों में हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देने के लिए सदस्यों को भुगतान करता था। रिपोर्ट में अनुसार गैंग कम खर्च में अपराध करवाने के लिए ऐसे युवाओं को निशाना बनाता था, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हों या जल्दी पैसे कमाने की चाह रखते हों।

जांच में यह भी सामने आया कि गुजरात की साबरमती जेल में

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में किसानों की बाइक रैली

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पंजाब के किसानों ने सोमवार को चंडीगढ़ में जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने अपनी एकजुटता और विरोध दर्ज कराने के लिए बाइक रैली निकाली, जिससे शहर के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहा। रैली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए चंडीगढ़ और मोहाली पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए तथा कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट करना पड़ा।

किसानों की बाइक रैली सुबह मोहाली के फेज-8 स्थित नेचर पार्क से शुरू हुई और चंडीगढ़ के सेक्टर-34 ग्राउंड तक पहुंची। बड़ी संख्या में किसान अपने साथ बाइक लेकर आए थे। कई किसान अपनी मोटरसाइकिलों को अन्य वाहनों



में लादकर रैली स्थल तक पहुंचे। रैली में शामिल किसानों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की। उनको कहना था कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का असर देश के कृषि क्षेत्र और किसानों की आय पर पड़ सकता है, इसलिए सरकार को किसानों के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

रैली के कारण सेक्टर-42 जंक्शन, सेक्टर-35 और 43 की डिवाइडिंग रोड, किसान भवन चौक सहित कई प्रमुख मार्गों पर लंबा जाम लग गया। कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों, आम नागरिकों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी देर हुई।

वेंडिंग जोनों की बदहाल स्थिति पर कमेटी करेगी जमीनी निरीक्षण

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

शहर में वेंडिंग जोन और मॉडल वेंडिंग जोन की बदहाल स्थिति को देखते हुए नगर निगम ने उनकी समीक्षा के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी विभिन्न सेक्टरों में जाकर वेंडिंग जोन का मौके पर निरीक्षण करेगी और उनकी वास्तविक स्थिति का आकलन करेगी। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाएगा कि मौजूदा वेंडिंग जोन को किसवित किया जाए या नए स्थानों को अंतिम रूप दिया जाए।

जानकारी के अनुसार शहर के कई सेक्टरों में वेंडिंग जोन के नाम के बोर्ड तो लगाए गए हैं, लेकिन जमीन पर उनकी स्थिति बेहद खराब है। कई स्थानों पर फेंसिंग के भीतर घास-फूस और झाड़ियां उग आई हैं, जिससे वहां काम करना तो दूर, पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में वेंडरों का कहना है कि यदि उन्हें इन स्थानों पर बैठना पड़े तो ग्राहकों का वहां तक



पहुंचना आसान नहीं होगा। विशेष रूप से सेक्टर-52 और सेक्टर-49 के वेंडिंग जोन की स्थिति काफी चिंताजनक बताई जा रही है।

नगर निगम की टाउन वेंडिंग कमेटी ने निर्णय लिया है कि 18 जुलाई को वेंडरों के लिए ड्रां आयोजित किया जाएगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से पात्र वेंडरों को नई साइटें और वेंडिंग जोन आवंटित किए जाएंगे। ड्रां के बाद यह होगा कि किस वेंडर को किस स्थान पर कारोबार करने की अनुमति मिलेगी। इसके साथ ही गठित कमेटी नई

प्रस्तावित साइटों का भी निरीक्षण करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं और वेंडर आसानी से अपना कारोबार कर सकें।

अधिकारियों का कहना है कि निरीक्षण के दौरान सड़क संपर्क, ग्राहकों की पहुंच, साफ-सफाई, सुरक्षा, पेयजल, रोशनी और अन्य आवश्यक सुविधाओं का भी मूल्यांकन किया जाएगा। यदि किसी वेंडिंग जोन में कमियां पाई जाती हैं तो उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

मोहाली पुलिस ने 63 मामलों के जब्त नशीले पदार्थ किए नष्ट

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली।

मोहाली जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मोहाली पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दर्ज 63 मामलों में बरामद नशीले पदार्थों का कानूनी प्रक्रिया के अनुसार निस्तारण किया। यह कार्रवाई ड्रा डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए संपन्न कराई गई। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिले में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान आगे भी

नशीला सिरप शामिल है। इन सभी नशीले पदार्थों को अदालत से आवश्यक अनुमति मिलने और सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सुरक्षित तरीके से नष्ट किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि



♦ जब्त मादक पदार्थों का सुरक्षित निस्तारण कर पुलिस ने दिया बड़ा संदेश

पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा।

पुलिस के अनुसार नष्ट किए गए मादक पदार्थों में 2 किलो 98 ग्राम हेरोइन, 25 किलो 900 ग्राम पोस्त धुन्करी, 21,570 नशीली गोतियां, 2,304 नशीले कैप्सूल, 39 किलो 844 ग्राम गांजा, 9 किलो 300 ग्राम चरस तथा 55 बोटल

जब्त किए गए मादक पदार्थों का समयबद्ध और सुरक्षित निस्तारण इसलिए आवश्यक है ताकि कोई भी प्रतिबंधित पदार्थ दोबारा अवैध बाजार तक न पहुंच सके। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया नशा तस्करों पर प्रभावी निंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

ढकोली सड़क पर पड़े बिजली के खंभों से बढ़ा हादसों का खतरा

भारतेन्दु संवाददाता, जीरकपुर

ढकोली क्षेत्र में गुलमोहर ट्रेड्स सोसाइटी और सॉलितेयर डिवाइन सोसाइटी के बीच स्थित सड़क पिछले करीब एक सप्ताह से लोगों के लिए परेशानी और खतरे का कारण बनी हुई है। सड़क के बीचोंबीच बिजली के खंभे पड़े होने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस लापरवाही के कारण हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, लेकिन संबंधित विभाग अब तक इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।

क्षेत्रवासियों के अनुसार सड़क पर पड़े इन खंभों के कारण कार पहिया वाहनों के निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं बची है। वाहन चालकों को सड़क के संकरे हिस्से से सावधानीपूर्वक गुजरना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि खंभों से निकली लोह की तारें सड़क पर फैली हुई हैं, जो आसानी से दिखाई नहीं देती। ऐसे में वाहन चेतें ही इनके ऊपर से गुजरते हैं, तार सीधे टायरों में धंस जाती हैं और टायर फट जाते हैं।



स्थानीय निवासियों ने बताया कि पिछले चार दिनों में ही सात से अधिक वाहनों के टायर फट चुके हैं। इससे वाहन मालिकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। कई बार वाहन अचानक असंतुलित होने की स्थिति में भी बनी, हालांकि अब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि यदि सड़क पर पड़े इन खंभों को नहीं हटाया गया तो भविष्य में कोई गंभीर दुर्घटना हो सकती है।

दलबीर सिंह, यशपाल, रमेश धीमान, केआर शर्मा सहित अन्य निवासियों ने बताया कि उन्हें अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि

सड़क पर पड़े ये खंभे बिजली विभाग के हैं या नगर परिषद के। इस कारण जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार संबंधित अधिकारियों से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी अधिकारी ने फोन उठाना उचित नहीं समझा। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

क्षेत्रवासियों का कहना है कि सड़क का यह हिस्सा दोनों सोसाइटियों के निवासियों के अलावा आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए भी प्रमुख मार्ग है। सुबह और शाम के समय यहां वाहनों की आवाजाही अधिक रहती है।



का उपयोग मंडी निर्माण में किया जाए, ताकि परियोजना के लिए अलग से ऋण लेने की आवश्यकता न पड़े।

कृषि विभाग के सचिव डी. कार्तिकेयन की अध्यक्षता में परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए प्रत्येक सप्ताह बैठकें आयोजित की जा रही हैं। अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने और सभी

मंडी के स्थानांतरण की प्रक्रिया होगी शुरू

नई मंडी निर्माण को रफ्तार

प्रशासन का मानना है कि नई अनाज मंडी के शुरू होने से किसानों, आदतियों और व्यापारियों को आधुनिक एवं बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वर्तमान सेक्टर-26 मंडी में जगह की कमी, बढ़ते यातायात दबाव और पार्किंग की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। नई मंडी में चौड़ी सड़कें, पर्याप्त पार्किंग, सुव्यवस्थित दुकानें, आधुनिक गोदाम, बेहतर जल निकासी व्यवस्था तथा डिजिटल सुविधाओं का भी प्रावधान किया जा रहा है। इससे कृषि उपज की खरीद-बिक्री अधिक व्यवस्थित और सुचारु ढंग से हो सकेगी। अधिकारियों के अनुसार परियोजना को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा ताकि निर्माण कार्य की पर्याप्त निगरानी संभव हो सके।

परियोजना की डीपीआर और नैवारण के अनुसार नष्ट किए गए मादक पदार्थों में 2 किलो 98 ग्राम हेरोइन, 25 किलो 900 ग्राम पोस्त धुन्करी, 21,570 नशीली गोतियां, 2,304 नशीले कैप्सूल, 39 किलो 844 ग्राम गांजा, 9 किलो 300 ग्राम चरस तथा 55 बोटल

बोर्ड का कार्यालय भवन और मार्केट कमेटी का कार्यालय भी बनाया जाएगा। कार्यालय भवनों पर क्रमशः लगभग 13.50 करोड़ और 9.60 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

परियोजना की डीपीआर नेबकन कंपनी ने तैयार की है। कृषि विभाग ने निर्माण लागत कम करने का सुझाव दिया था, लेकिन विस्तृत अध्ययन के बाद कंपनी ने

